(b) and (c) Information has been called for from the Government of Andhra Pradesh and will be laid on the table of the House on its receipt.

(d) Yes, Sir.

(e) Report has already been asked for from the Government of Andhra Pradesh.

ITDA Loan for Tobacco Barn Construction in A. P.

3575. SHRI V. HANUMANTHA RAO : Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) the directions given to Integrated Tribal Development Authority (ITDA) to carefully weigh and watch the type of the programmes for the economtc betterment of tribals ;

(b) whether it is a fact that the ITDA in Andhra Pradesh has extended vast subsidies for tobacco barn construction;

(c) how much money was released for tobacco barn construction by the ITDAs in Andhra Pradesh in West Godavari district and Khamman District between 1990-91. 1991-92 and 1992-93; and

(d) how many of these tobacco barns have been actually built and owned and operated by tribals ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRI K. V. THANGKA BALU) : (a) No such specific directions have been given. However, instructions have been issued from time to time to the State Government by the Ministry of Welfare to ensure that viable family oriented income generating schemes are taken up under Special Central Assistance to the Tribal Sub-Plan for the economic develop-ment of tribal families.

(b) to (d) Information has been called for from the Government of Andhra Pradesh and will be laid on the Table of the House as soon as it is received.

Guidelines to Tribal Welfare Commissioners for Sanctioning and Distributing Loans

3576. SHRI V. HANUMANTHA RAO : Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that clear guidelines have been issued to respective Commissioners of Tribal Welfare of the State Governments in sanction and distribute loans to tribals after proper scrutiny;

(b) if so, the details of such guidelines ;

(c) whether it is a fact that many ordinary tribals in some parts of Andhra Pradesh have never received any benefit from the ITDA ever since inception of ITDA programmes

(d) whether directions will be given to the State Governments that assistance must be uniformly and judicially distributed;

(e) whether Government propose to make a special reference to Government of Andhra Pradesh to note the cornering of loans by a few people in tribal areas in West Godavari; and

(f) measures proposed to Tribal Welfare Commissioner in Andhra Pradesh to rectify this situation ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRI K. V. THANGKA BALU): (a) and (b) Loans are disbursed by banks and subsidy is released by ITDAs/ITDPs in family oriented income generating schemes under Special Central Assistance to Tribal Sub-Plan. The banks are expected to scrutinise loan applications. State Governments have been advised to follow IRDP guidelines regarding pattern of subsidy.

(c) Information has been sought for from the Government of Andhra Pradesh and will be laid on the table of the House on its receipt.

(d) Yes, Sir. Appropriate instructions will be issued to the State Government in this regard.

- (e) Yes, Sir.

(f) Tribal Welfare Commissioner Andhra Pradesh, will specifically be requested to ensure that IRDP guidelines, are strictly followed for sanction of loan and distri-

bution of subsidies under SCA to TSP meant for individual family oriented income generating Schemes..

संसद सदस्यों का पत्राचार

3577. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 जुलाई, 1992 से 31 मार्च, 1993 तक संसद सदस्यों से लगभग 500 पत्र प्राप्त हुए थे । और उनमें से केवल 475 पत्रों की पावतियां ही भेजी गई थी और केवल 74 पत्रों के उत्तर अंतिम रूप से दिये गये थे ;

(ख) क्या सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है जिन्होंने इन पत्रों की प्राप्ति से तीन महीने के भीतर अंतिम रूप से उत्तर नहीं भेजे थे ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(घ) इन अधिकारियों में से उन अधिकारियों की संख्या कितनी है जिनके खिलाफ अब तक कार्यवाही की गई है?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० वी० तंगकाबालू) :

(क) पहली मार्च, 1992 से 31 मार्च, 1993 की अवधि के दौरान 561 पत्र प्राप्त हुए थे और 524 पत्रों के अंतिम उत्तर भेजे गए थे । केवल 37 पत्र लंबित है ।

(ख), (ग) और (घ) संसद सदस्यों को अंतिम उत्तर भेजने में विलम्ब का कारण राज्य सरकारों संघ राज्य क्षेत्रों से मांगी गई सूचना प्राप्त न होना है । कुछ मामलों में संसद सदस्य योजनाओं में कुछ संशोधनों का सुझाव देते हैं, जिसे संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष उठाया जाता है और अंतिम उत्तर सुझावों पर सरकार द्वारा कोई निर्णय लिए जाने के बाद ही दिए जा सकते हैं ।

पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण

3578. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण के अन्तर्गत 31 जनवरी 1994 तक कोई नियुक्ति नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० वी० तंगकाबालू) : (क) जी, हां । तथापि अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित कोटे के सम्मुख प्रथम नियुक्ति एक उम्मीदवार को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम में सहायक प्रबंधक के पद पर नियुक्त करते हुए की गई ।

(ख) और (ग) आरक्षित कोटे में अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों की भर्ती निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जानी है, जिसमें समय लगेगा । चूंकि 8 सितम्बर, 1993 का कार्यालय ज्ञापन उन पदों पर लागू नहीं होता जिनकी भर्ती-प्रक्रिया पहले ही अर्थात् 8 सितम्बर, 1993 के पूर्व शुरू की जा चुकी थी; अतः आरक्षण का लाभ अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को शीघ्र ही उपलब्ध नहीं कराया जा सका ।

संघ लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने संबंधी प्रमुख परीक्षाओं की अधिसूचना पहले ही जारी कर दी है ।

भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों तथा वित्तीय संस्थानों को भी अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु लिखा जा चुका है ।